which has been taking place on a large-scale and to which attention of the Government has been drawn I want to know what has been done with regard to that so far.

Shri Annasahib Shinde: I have no information about this smuggling into Jammu and Kashmir. But I will get in touch with the Jammu and Kashmir Government. About Himachal Pradesh, I may submit we have not effected any reduction in the quota which is being supplied to Himachal Pradesh.

श्री मीतिराम सिंह चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जो कोटा है क्या उस में भी कोई कमी की गई है और यदि की गई है तो वहां की गम्भीर खाद्य स्थिति को देखते हुए क्या उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा ?

Shri Annasahib Shinde: Even in regard to Madhya Pradesh, taking into consideration the considerable distress prevailing in Madhya Pradesh, we have not effected any cut there.

Criteria to Determine Scarcity and Famine Areas

\+

*606. **Shri George Fernandes:**
Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have laid down new criteria for distinguishing 'scarcity', 'actute scarcity' and 'famine' areas;

(b) whether the criteria set out by Government as outlined by the former Food Minister stand cancelled; and

(c) if so, the basis of the new criteria?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D. Ering): (a) and (b). There is no Famine Code of India and no formal cretaria have been laid down by the Central Government in this respect. The criteria for distinguishing the degrees of distress are a matter for the State Governments.

(c) Does not arise.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हमारे देश में अकाल की परिस्थिति हमेशा बनी रहती है और हर साल काफी लोग अकाल से मर जाते हैं। यह कहा जाता है सियासी पार्टीज की ओर से ही नहीं बल्कि सर्वोदयी मंडल जैसी संस्थाओं की ओर से भी कि लोग अकाल से मरते हैं। सारी दुनिया में इस बात का प्रचार होता रहता है कि अकाल की वजह से इस मुल्क में लोग मर रहे हैं। क्या सरकार उचित नहीं समझती है कि अखिल भारतीय पैमाने पर एक फैमिन कोड बनाया जाए और जो भी कसौटियां लगानी हैं, उनको लगा दिया जाए ताकि सूबे और केन्द्र के बीच में अकाल के मसले को लेकर जो हमेशा टकराव होता है वह खत्म हो जाए ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): Preparation of famine code, scarcity manuals, etc. falls within the competence and jurisdiction of the State Governments. The hon. Member's question can be taken as a suggestion for action.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : बिहार में नई सरकार के निर्माण के बाद बिहार के कई इलाकों को उसने अकाल ग्रस्त इलाके घोषित किया है। जब उसने ऐसा किया था तब केन्द्र की ओर से काफी शोरगुल भी किया गया था। यह कहा गया था कि अकाल की परिस्थिति न होते हुए भी वहां पर अकाल की परिस्थिति है, ऐसा घोषित कर दिया गया है। यह भी कहने में आया था कि केन्द्र को बदनाम करने के लिए सूबे की सरकार की ओर से ये इलाके अकाल ग्रस्त इलाके घोषित किए गए हैं। अभी जैसा मंत्री

महोदय ने कहा है अखिल भारतीय पैमाने पर कोई फैमिन कोड नहीं है और कोई भी सूबा अपने किसी भी इलाके को अकालग्रस्त इलाका अथवा अभाव का इलाका घोषित करता है तो केन्द्र की ओर से यह जो तकलीफ या यह जो हरकत उठाने में आ जाती है यह किस आधार पर आ जाती है

Shri Annasahib Shinde: As I have already mentioned, declaration of famine, scarcity, etc. falls within the competence and jurisdiction of the State Governments and the State Governments are fully competent to declare any area as famine area, scarcity area or acute scarcity area. But sometimes if the State Governments asks for our advice and if, suppose, we give some advice, I do not think that the hon. Member should be angry about that.

श्री जार्ज फरनेन्डीज मेरा प्रश्न यह था कि बिहार सरकार ने कई इलाकों को अकालग्रस्त इलाके घोषित किया । तब केन्द्र की ओर से यह कहा गया कि आप गलती कर रहे हैं और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि वह बात आपने किस आधार पर कही जबकि आपके पास कोई भी कोड नहीं है ?

Shri Annasahib Shinde: I have already replied Our advice was not binding on the Bihar Government. The Bihar Government was fully competent to declare any area as famine area. My only submission is that we thought that as a result of declaration of famine, no further financial or other benefits were likely to accrue to Bihar Government. Perhaps it may be that the price level may be affected adversely all over the country. That was our view. But the Bihar Government was fully competent to declare any area as famine area. We have never come in their way.

श्री रामानन्द शास्त्री : क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बिहार की नई सरकार ने फैमिन कोड में कई परिवर्तन किए हैं? कई संशोधन किये हैं ? अगर है तो क्या आप भी उन संशोधनों के आधार पर कोई फैमिन कोड बनाने की बात अथवा फैमिन कोड में संशोधन करने की बात अखिल भारतीय पैमाने पर करने की सोच रहे हैं ?

Shri Annasahib Shinde: I have no information whether any amendment has been made by the Bihar Government in their famine cote. As far as the famine code of India is concerned I have already said in the main answer that there is no famine code of India at the present moment.

श्री शरद यादव यह बात सही है कि किसी इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित करना सूबाई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज यह खाद्य समस्या और खाद्यान्नों का अभाव पूरे देश में व्याप्त है और इस समस्या के बारे में केन्द्रीय सरकार समय समय पर खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन भी करती रहती है, तमाम हिन्दुस्तान के खाद्य मंत्रियों को बुला कर सम्मेलन भी करती रहती है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो फैमिन कोड बना हुआ है वह पचास साल पहले बना था या उससे भी पहले बना था और उस में जो क्राइटीरिया दिये गये हैं वे आज की स्थिति में लागू नहीं होते हैं, क्या खाद्य मंत्रियों का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उस में आप अपनी ओर से कुछ ऐसा सुझाव प्रस्तुत करेंगे ताकि जो क्राइटीरिया है किसी इलाके को सूखा ग्रस्त या अकाल ग्रस्त घोषित करने का, वह एक समान हो ताकि पूरे देश में इस मामले में यूनिफार्मिटी लाई जा सके ?

Shri Annasahib Shinde: It is a suggestion for action.

श्री रामसेवक यादव : बिहार के कई इलाकों में अकाल की घोषणा कर दी गई है, कई इलाकों को अकाल ग्रस्त इलाके घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में हालत कहीं कहीं बहुत ही खराब है लेकिन वहां पर अकाल की घोषणा नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि भिन्न भिन्न राज्यों में अभाव, अधिक अभाव तथा अकाल की परिभाषायें और उनके मापदंड अलग अलग हैं, यदि हां, तो क्या एक जैसा मापदंड हो इसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं ताकि सब को समान रूप से सहूलियतें दी जा सकें ?

Shri Annasahib Shinde: I have already mentioned that is is a State subject. All these are suggestions for action.

श्री रामसेवक यादव : स्टेट सबजेक्ट तो है। मैं ने कहा है कि हर राज्य में अभाव, भारी अभाव तथा अकाल ग्रस्त, इनके मापदंड अलग अलग हैं, भिन्न हैं। इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। इसको वह बतलाने की कृपा करें।

Mr. Speaker: I think the hon. Minister has no answer for that.

Shri Ram Kishan: May I know, if under the criteria laid down by the Central Government, some parts of Himachal Pradesh have been declared acute scarcity areas. If so, what type of aid is being given to those areas of Himachal Pradesh, and if no aid is being given, why not?

Shri Annasahib Shinde: As I have already mentioned, we are allocating about 6,000 tonnes of foodgrains to Himachal Pradesh. We have not effected any cut in the supplies to Himachal Pradesh though we are in a tight position as a result of difficulties created by scarcity. If any area is affected by drought etc., it is a well-established practice that over and above the normal supplies made to the State Gover ent, according to the pattern of assistance suggested by the Finance Commission, the Centre can give assistance to Himachal Pradesh also.

Rice Requirement of Kerala

+

***607. Shri Sradhakar Supakar:**
Shri M. Sudrasanam:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Kerala has suggested that if the Centre was not in a position to supply rice in adequate quantities, Kerala must be allowed to utilise some of the foreign exchange earned by Kerala for purposes of import of rice; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering): (a) No, Sir. No such suggestion has been received by the Central Government.

(b) Does not arise.

Shri Sradhakar Supakar: There was a widespread view reported in the newspapers, and while answering the general debate in this House, the Food Minister himself had also stated that Government of India would tap those sources which the Chief Minister of Kerala had indicated...

Mr. Speaker: The hon. Minister has denied it; he has said that no such suggestion has been made.

Shri Sradhakar Supakar: But some time back.... .

Mr. Speaker: That was there in the newspapers. But the hon. Minister has denied that.

Shri Sezhiyan: The hon. Member is referring to the speech made by the